

**उत्तराखण्ड शासन**  
**राजस्व अनुभाग-3**  
**संख्या: 203/XVIII(3)/2017-02(46)2017**  
**देहरादून: दिनांक: 23 मई, 2017**

**अधिसूचना**

चूंकि समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के लिए जनपद टिहरी में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक अर्थात् 144.077 एकड़ (58.321 है०) है;

अतः अब श्री राज्यपाल, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 45(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए सम्बन्धित कलक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- राज्यपाल उप धारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्-

- (क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि;
- (ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;
- (ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि;
- (घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि;
- (ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी;
- (च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती;
- (छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;
- (ज) सम्बन्धित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधान सभा का सदस्य या उनके नामनिर्देशिती;
- (झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि; और
- (ञ) सदस्य-संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।

हरबंस सिंह चुघ  
प्रभारी सचिव।

**संख्या- 203(1)/XVIII(3)/2017 तददिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि०, ऋषिकेश।
9. जिलाधिकारी, टिहरी।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को मुद्रित कराकर 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)  
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "**the Constitution of India**", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 203 dated for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND  
RAJASWA ANUBHAG  
No. 203 /XVIII(III)/2017-02(46)/2017  
DEHRADUN: DATED: 23, May, 2017

**NOTIFICATION**


Whereas the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre i.e. 144.077 acre (58.321 Hac.) in Distric Tehri for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No.30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Gram Sabha in Rural areas and Nagar Palika in the Urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme.

2- The Governor is pleased also directed under sub-section (2) that in addition of the officers of the appropriate Government the following members shall be the member of the rehabilitation and resettlement committee—

- (a) a representative of women residing in the affected area;
- (b) a representative each of the scheduled castes and the scheduled tribes residing in the affected area;
- (c) a representative of a voluntary organisation working in the area;
- (d) a representative of a nationalised bank;
- (e) the Land Acquisition Officer of the project;
- (f) the Chairpersons of the panchayats or municipalities located in the affected area or their nominees;
- (g) the Chairperson of the District Planning Committee or his nominee;
- (h) the Member of Parliament and member of the Legislative Assembly of the concerned area or their nominees;
- (i) a representative of the Requiring Body; and
- (j) a administrator for Rehabilitation and Resettlement as the Member- Convenor.

By order,

  
(Harbans Singh Chugh)  
Secretary In-charge